भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 647
दिनांक 28 नवम्बर, 2024

राजकोट में कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना

†647. श्री परषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडारों में सुधार लाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त पहलों से क्या वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं;
(ग) देश में कच्चे तेल के भंडारों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा राजकोट में कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की स्थापना के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने इण्डियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजनार्थ कंपनी के माध्यम से तीन स्थलों यथा, (i) विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी), (ii) मंगलुरू (1.5 एमएमटी) और (iii) पादुर (2.5 एमएमटी) में कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की क्षमता वाले कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) सुविधाओं की स्थापना की है। यह लगभग 9.5 दिनों के लिए कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करेगा।

जुलाई, 2021 में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर ओडिशा के चंडीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक सह कार्यनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व सुविधाओं की स्थापना को भी अनुमोदित किया था। सरकार तथा ओएमसीज समय-समय पर तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर भंडारण क्षमता के संवर्धन की संभावनाओं का मूल्यांकन करती हैं।

अप्रैल/मई 2020 में कच्चे तेल के कम मूल्यों का लाभ उठाते हुए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता को पूरी तरह से भर दिया गया था जिससे लगभग 5000 करोड़ रूपए की अनुमानित बचत हुई है। इसके अलावा, सरकार ने वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) कार्यक्रम चरण-I के तहत सृजित पेट्रोलियम रिज़र्व के कुछ भाग का उपयोग करने हेतु आईएसपीआरएल को स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके तहत आईएसपीआरएल द्वारा भारतीय कंपनियों को कंदराओं की समग्र तेल भंडारण क्षमता के 20% की बिक्री/खरीद के साथ-साथ भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों को कंदराओं की समग्र तेल भंडारण क्षमता का 30% पट्टे पर/ किराए पर देने की अनुमति दी गई है। पट्टे पर दिए जाने वाले कच्चे तेल की बिक्री से हासिल प्राप्तियां, सरकार को लौटाई जा रही है।

वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण संबंधी कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिन को कवर करती है जिसमें तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की 64.5 दिनों की भंडारण सुविधा क्षमता शामिल है।

(घ): अतिरिक्त पेट्रोलियम रिज़र्व की स्थापना हेतु नए स्थलों का आकलन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

****